IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, January 2026
Impact Factor: 8.2

आधुनिक भारत में औद्योगिक क्रांति का सामाजिक ढांचे पर प्रभाव और वर्ग-व्यवस्था में परिवर्तन का विश्लेषण

चंचल सिंह बोरा[1] and डॉ. सुरेश चंद[2]

[1]शोधार्थी, इतिहास-विभाग

[2]शोध निर्देशक, इतिहास-विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश

आधुनिक भारत में औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक संरचना, वर्गीय विभाजन, आर्थिक अवसरों और शहरी जीवन शैली में गहन परिवर्तन उत्पन्न किए। पारंपरिक जाति-आधारित समाज से श्रम-आधारित आधुनिक वर्ग संरचना उभरी, जिसने उत्पादन संबंधों, सामाजिक गतिशीलता, शहरीकरण और श्रमिक पहचान को पुनः परिभाषित किया। यह समीक्षा-पत्र भारत में औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप वर्ग-व्यवस्था के बदलाव और सामाजिक ढांचे पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जहाँ औद्योगिक पूंजीवाद, श्रमिक वर्ग निर्माण और शहरी समाज की जटिलताओं पर विशेष बल दिया गया है।

मुख्य संकेतक: श्रमिक वर्ग, पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजी, आर्थिक असमानता

परिचय

18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने भारत को विश्व के सामाजिक-आर्थिक वर्गीय एक नये औद्योगिक समाज में बदल दिया। भारत में यह परिवर्तन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान धीरे-धीरे शुरू हुआ, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण, रेलवे विकास, कपड़ा मिलों के प्रतिष्ठान और कारखाने-आधारित उत्पाद प्रणाली ने श्रमिक वर्गों का विस्तार और नई सामाजिक पहचान को जन्म दिया (रॉय, 2016)। शास्त्रीय अनुष्ठान और जमींदारी-वर्ग

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

संरचना धीरे-धीरे-आध्यात्मिक वर्ग डिवीजन में बदल दी गई, जिसने भारत के सामाजिक वर्गीकरण को पुनर्गठित किया।

औद्योगीकरण और पारंपरिक सामाजिक ढांचे का विघटन

भारत में औद्योगीकरण केवल आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह सामाजिक संरचना के व्यापक विखंडन, पुनर्गठन और नयी सामाजिक पहचान निर्माण का आधार भी बना। पारंपरिक भारतीय समाज सदियों तक जाति-आधारित, कृषि-प्रधान, तथा परिवार-नियंत्रित उत्पादन प्रणाली पर आधारित रहा, जहाँ सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म-आधारित जाति, कुलीनता, भूमि-स्वामित्व और परंपरागत व्यवसाय से होता था। किंतु 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के विस्तार ने इन गतिशीलताओं को उलटते हुए समाज को एक नए वर्ग-आधारित ढांचे में रूपांतरित किया, जहाँ श्रम-बाजार, नगरीय विकास, पूंजी संचय तथा अनुबंधित श्रमिक व्यवस्थाओं ने सामाजिक संबंधों और पहचान को पुनर्परिभाषित किया।

औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के उदय से पहले ग्रामीण भारत में सामाजिक भूमिकाएँ परंपरा, जाति-व्यवस्था और वंशानुक्रमित पेशों पर निर्भर थीं। उदाहरणस्वरूप, लोहार, कुम्हार, नाई, जुलाहा, सुनार, किसान, जमींदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि व्यवसाय और जाति पहचान परस्पर जुड़ी हुई थीं।

किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसी जन्मगत संरचना में स्थिर रहती थी। आर्थिक गतिशीलता का अवसर सीमित था क्योंकि कृषि उत्पादन, जमीन स्वामित्व और कृषिजन्य कराधान ही आय के मुख्य साधन थे। लेकिन कारखानों, मिलों, रेलवे, कोयला खदानों, लौह-इस्पात उद्योगों और कपड़ा उद्योग के विकास के बाद श्रम-आधारित उत्पादन प्रणाली ने जन्म आधारित कार्य-निर्धारण की जगह आर्थिक योग्यता, मजदूरी और श्रम क्षमता को प्राथमिक तत्व बनाया। पारंपरिक जाति-पेशागत ढांचा इस प्रकार क्षीण होने लगा और श्रमिक वर्ग की नई पहचान उभरकर सामने आई।

शहरीकरण औद्योगिक विकास का प्रमुख परिणाम था, जिसने पारंपरिक ग्रामीण-आधारित जीवन शैली, संयुक्त परिवार प्रणाली और सामाजिक नियंत्रण संरचनाओं को प्रभावित किया। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, कानपुर, अहमदाबाद जैसे औद्योगिक महानगरों ने ग्रामीण श्रमिकों, प्रवासियों और आर्थिक अवसर खोजने वाले युवाओं के लिए आकर्षण केंद्र का निर्माण किया। इन शहरों में कारखाना कॉलोनियों, श्रमिक बस्तियों, चॉल व्यवस्था और झुग्गियों ने मिश्रित जातीय और वर्गीय सामाजिक समूहों को एक साझा आर्थिक ढांचे में समाहित किया। इससे जातिगत दूरी कम हुई, अंतर्सामुदायिक संपर्क बढ़ा और सामाजिक गतिशीलता

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

का दायरा विस्तृत हुआ। गाँव-आधारित सामाजिक नियंत्रण, जाति पंचायतें और सामाजिक अनुशासन की पारंपरिक व्यवस्थाएँ शहरी क्षेत्रों में उतनी प्रभावी नहीं रहीं, क्योंकि श्रम-आधारित शहरों में व्यक्ति की पहचान उसकी उत्पादन क्षमता, मजदूरी और श्रम-घंटों पर आधारित हो गई थी।

इसी के साथ औद्योगिक पूंजीवाद ने सामाजिक ढांचे में शक्ति-संतुलन का स्थानांतरण भी किया। भूमि-स्वामी वर्ग, जमींदार प्रभुत्व और पारंपरिक जातीय श्रेष्ठता में कमी आई क्योंकि नए पूंजीपति वर्ग, व्यापारिक उद्यमी और प्रबंधकीय अधिकारी सामाजिक संरचना के शीर्ष पर स्थानांतरित होने लगे। इस आर्थिक पुनर्गठन से एक नया मध्यम वर्ग भी उभरा, जिसमें तकनीकी-कुशल कर्मचारी, कार्यालय कर्मी, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और सरकारी अधिकारी शामिल थे। इस वर्ग ने शिक्षा, नगरीय जीवन, उपभोक्तावाद और आधुनिक मूल्यों को सामाजिक सम्मान का आधार बनाया, जिसके फलस्वरूप जन्म-आधारित श्रेणी निर्धारण की जगह उपलब्धि-आधारित सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण बन गई।

महिला श्रम भागीदारी भी पारंपरिक सामाजिक ढांचे के विघटन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम था। औद्योगिक कारखानों, वस्त्र उद्योगों, सेवा क्षेत्रों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति ने पितृसत्तात्मक नियंत्रण को चुनौती दी। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा प्राप्ति और कार्यस्थल सहभागिता ने पारिवारिक भूमिकाओं और लैंगिक सामाजिक सीमाओं को भी पुनर्परिभाषित किया। इससे विवाह-आधारित नियंत्रण, दहेज-प्रथा, घरेलू कैद और सामाजिक निर्भरता की पारंपरिक संरचनाओं में ढील आई।

औद्योगीकरण ने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के क्षेत्र में भी परिवर्तन उत्पन्न किए। औद्योगिक शहरों में बहु-सांस्कृतिक, बहु-धार्मिक श्रमिक समूहों के एकत्रीकरण ने सांस्कृतिक समन्वय, सामूहिकता और सह-अस्तित्व के अवसर बढ़ाए। जाति और धर्म पर आधारित सामाजिक अलगाव का प्रभाव कमजोर हुआ और उसकी जगह कार्यस्थल, मजदूरी और जीवन-यापन की सामूहिक चुनौतियों ने सामाजिक एकता के नए आयाम प्रस्तुत किए।

हालाँकि पारंपरिक ढांचे के इस विघटन के साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं। शहरी गरीबी, बेरोजगारी, असंगठित श्रम, प्रवासी असुरक्षा, निम्न-आवास व्यवस्था और औद्योगिक शोषण जैसे मुद्दों ने वर्ग-आधारित असमानता को जन्म दिया। सामाजिक असमानताएँ जाति से हटकर वर्ग-आर्थिक स्तर पर स्थानांतरित हो गईं। अब ऊँच-नीच का निर्धारण जन्म से नहीं, बल्कि वेतन, श्रम सुरक्षा, कौशल और पूंजी संचय से होने लगा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

औद्योगीकरण ने पारंपरिक जाति-आधारित और भूमि-प्रधान सामाजिक संरचना को विघटित करते हुए आधुनिक वर्ग-आधारित, शहरी और श्रम-निर्धारित पहचान की ओर भारत को निर्देशित किया। इस प्रक्रिया में सामाजिक गतिशीलता, श्रमिक वर्ग का विकास, नगरीय संस्कृति, शिक्षा, लैंगिक भूमिका परिवर्तन और आर्थिक पुनर्गठन शामिल रहा, जिसने भारतीय समाज को स्थिरता से गतिशीलता, परंपरा से आधुनिकता और जाति से वर्ग ढांचे की ओर स्थानांतरित कर दिया।

भारतीय समाज लंबे समय तक जाति-आधारित संरचना द्वारा संचालित रहा। औद्योगीकरण ने इस व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन उत्पन्न किए:

1. उत्पादन संबंध जाति आधारित नहीं बल्कि पूंजी और श्रम आधारित हुए
2. ग्रामीण आधारित सामाजिक पहचान शहरी पहचान में बदली हुई
3. जातीय व्यावसायिक बंधन में कमी आई (बेली, 2004)
4. औद्योगिक पूंजीवाद ने श्रमिक वर्ग को जाति सीमा से परे आर्थिक इकाई के रूप में परिभाषित किया (चंदावरकर, 1994)।

नये श्रमिक वर्ग का उदय और वर्गीय पुनर्गठन

औद्योगिक समाज की नींव पैसे आधारित श्रम बाजार के निर्माण में निहित थी:

1. दैनिक मजदूरी, निश्चित मजदूरी और अनुबंध श्रम का विस्तार
2. कारखानों में श्रमिक वर्ग की स्थायी पहचान
3. पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली द्वारा वर्गीय विभाजन की स्थापना

पैरी (2013) के अनुसार, भारत में श्रमिक वर्ग ने शहरी केंद्रों में आर्थिक अवसर के साथ एक नई वर्ग चेतना विकसित की जिसका संबंध जाति की बजाय श्रम, मजदूरी और आर्थिक गतिशीलता से था।

शहरीकरण और सामाजिक गतिशीलता का विस्तार

शहरीकरण औद्योगिक क्रांति की सबसे प्रमुख देन है:

1. जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवाहित हुई
2. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर जैसे शहर औद्योगिक केंद्र बने
3. श्रमिक आवास, मजदूर कॉलोनी, चॉल प्रणाली और बस्तियाँ विकसित हुईं

डेविस (2006)का कहना है कि औद्योगीकरण के बाद शहरी समाज में जाति से अधिक आर्थिक स्तर सामाजिक स्थिति का निर्धारक बना, जिससे नई सामाजिक श्रेणियाँ विकसित हुईं:

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

1. औद्योगिक मध्यम वर्ग
2. तकनीकी-कुशल श्रमिक
3. असंगठित निम्न-वर्गीय मजदूर

महिलाओं और श्रमिकों की सामाजिक भूमिका में परिवर्तन

औद्योगीकरण और सामाजिक-आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक भारत में महिलाओं और श्रमिकों की भूमिकाओं में गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाएँ गृह-केन्द्रित भूमिकाओं में सीमित थीं, जिनका कार्य-क्षेत्र मुख्यतः परिवार संरचना, घरेलू उत्तरदायित्व, देखभाल, सामाजिक रीति-रिवाजों व सांस्कृतिक संरचनाओं तक सीमित था। दूसरी ओर श्रमिक वर्ग मुख्यतः कृषि आधारित सामंतवादी ढांचे में बंधा हुआ था, जिसके पास स्वायत्तता और आर्थिक गतिशीलता के अवसर सीमित थे। परंतु औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण, शिक्षा के प्रसार और पूंजीवादी उत्पादन संबंधों ने इन्हीं दोनों वर्गों की संरचना, स्थिति एवं भूमिका में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रथम, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक पहचान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कार्य ताकत में सहभागिता के रूप में परिलक्षित हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वस्त्र उद्योग, चाय बागान, तंबाकू उद्योग तथा प्रसंस्करण कारखानों में महिला श्रमिकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी। धीरे-धीरे सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, आईटी, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति स्थापित हुई। आर्थिक स्वतंत्रता और वेतन आधारित रोजगार ने महिलाओं को सामाजिक निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय किया और धीरे-धीरे पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती दी। आर्थिक आय के साथ परिवार में महिलाओं की निर्णयकारी भूमिका बढ़ी, जिससे परिवार संरचना में पारंपरिक "आय अर्जक पुरुष" और "गृह देखभाल करने वाली महिला" की धारणा कमजोर होने लगी।

द्वितीय, श्रमिक वर्ग की सामाजिक भूमिका भी औद्योगीकरण द्वारा परिवर्तित हुई। कृषि पर आधारित पारंपरिक श्रम प्रणाली से हटकर श्रमिक अब पूंजी-आधारित उत्पादन प्रणाली से जुड़ने लगे। इसे आर्थिक वर्ग चेतना और संगठित श्रमिक पहचान के रूप में पहचाना गया। फैक्ट्री आधारित श्रम संस्कृति, समय-निर्धारित मजदूरी, अनुबंध श्रम, प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादन और श्रम विभाजन ने श्रमिकों को समाज के एक संरचित आर्थिक वर्ग में बदल दिया। इसके साथ ही श्रमिक संघर्ष और ट्रेड यूनियनों का विस्तार हुआ, जिसने मजदूरी अधिकार, कार्य सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण और कार्य स्थितियों में सुधार की मांगों को बल दिया। औद्योगीकरण

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

के बाद श्रमिकों की सामाजिक भूमिका केवल उत्पादन के यंत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक आंदोलन और वर्गीय चेतना के प्रमुख कारक बने।

तृतीय, महिलाओं और श्रमिकों दोनों की भूमिकाओं में हुए परिवर्तन ने शहरी सामाजिक संरचना को भी परिवर्तित किया। शहरों में श्रमिक कॉलोनियां, औद्योगिक आवास, चॉल और बस्तियाँ विकसित हुईं जहाँ विविध जाति, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग साथ रहने लगे। इससे सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ी और पारंपरिक जाति आधारित व्यावसायिक सीमाएँ टूटने लगीं। कामकाजी महिलाओं की बढ़ती संख्या ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी नीतियों के क्षेत्र में सुधार की जरूरत को और प्रबल किया। महिला शिक्षा, प्रसूति अवकाश, समान वेतन कानून, महिला सुरक्षा कानून और कौशल विकास योजनाओं को इसी परिवर्तनशील सामाजिक प्रक्रिया का प्रतिफल माना जा सकता है।

चतुर्थ, कार्यस्थल की नयी परिभाषा ने महिलाओं और श्रमिकों दोनों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि ने सामाजिक समानता की अवधारणा को मजबूत किया, जबकि श्रमिक वर्ग की राजनीतिक और आर्थिक सक्रियता ने वर्गीय असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष को आकार दिया। यद्यपि अभी भी लिंग आधारित असमानता, कार्यस्थल हिंसा, वेतन अंतर, असंगठित श्रम और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, किन्तु इन समस्याओं पर सामाजिक संवेदना और नीतिगत हस्तक्षेप पहले की तुलना में अधिक सशक्त रूप में उपस्थित हैं।

वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद कार्य संस्कृति में हुए परिवर्तनों ने महिलाओं और श्रमिकों की भूमिकाओं को और अधिक लचीला, तकनीकी और कौशल आधारित बना दिया। अब "काम" केवल फैक्ट्री या कृषि भूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल, रिमोट कार्य, आईटी आधारित सेवाएँ, सूक्ष्म-व्यवसाय, स्वयं सहायता समूह और स्टार्ट-अप संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से विकसित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार, कार्यस्थल और समाज में महिलाओं और श्रमिकों की पहचान उत्पादक सामाजिक एजेंट के रूप में पुनर्स्थापित हुई।

आधुनिक भारत में औद्योगीकरण, शहरीकरण और पूंजीवादी आधुनिकीकरण ने महिलाओं और श्रमिकों की भूमिकाओं में पारंपरिक सीमाओं से परे व्यापक परिवर्तन किए। इन दोनों वर्गों की नई सामाजिक परिभाषा अब समानता, श्रम अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सहभागिता जैसे मानकों पर आधारित है, जिसने न केवल सामाजिक ढांचा बदला बल्कि लोकतांत्रिक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की दिशा को भी मजबूती प्रदान की।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

औद्योगीकरण ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाई:

1. वस्त्र कारखानों, औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में सहभागिता
2. आर्थिक स्वावलंबन और शिक्षा अवसरों का विस्तार

सेन (1999) के अनुसार, महिला श्रम भागीदारी ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे को चुनौती दी, जिससे परिवार संरचना और सामाजिक उत्तरदायित्व में परिवर्तन आए।

औद्योगिक पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष

औद्योगिक समाज में पूंजी और श्रम के बीच संघर्ष की स्थिति बढ़ी:

1. मजदूरी असमानता
2. कार्यस्थल असुरक्षा
3. सामाजिक सुरक्षा का अभाव

मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष सिद्धांत के अनुसार, औद्योगिक पूंजीवाद ने श्रमिक वर्ग को पूंजी निर्भर बना दिया, जिससे वर्गीय शोषण का स्वरूप मजबूत हुआ (हार्वे, 2011)।

इसी पृष्ठभूमि में भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन विकसित हुआ, जिसने वर्ग चेतना को राजनीतिक रूप प्रदान किया।

औद्योगिकीकरण और जाति से वर्ग में संक्रमण

भारतीय सामाजिक ढांचे में जाति-व्यवस्था का प्रभाव गहरा था, परंतु औद्योगिक कार्य संस्कृति ने इसे चुनौती दी:

1. फैक्ट्री आधारित श्रम बाजार में जाति-आधारित पेशा निर्धारण कमजोर हुआ
2. वर्गीय पहचान श्रम उत्पादकता, मजदूरी और आर्थिक स्थिति पर आधारित हुई
3. शहरी बहु-जातीय श्रमिक समूहों ने सामाजिक मिश्रण को बढ़ावा दिया (ओमवेट, 1994)

निष्कर्ष

औद्योगिक क्रांति ने भारत की सामाजिक संरचना, वर्गीय विभाजन और श्रम-आधारित सामाजिक पहचान को गहन रूप से परिवर्तित किया। पारंपरिक जाति और भूमि-आधारित सामाजिक व्यवस्था की जगह पूंजी, उत्पादन और आर्थिक अवसरों पर आधारित वर्गीय संरचना विकसित हुई। शहरीकरण, श्रमिक वर्ग निर्माण, महिला श्रम भागीदारी और यूनियन गतिविधियों ने न केवल सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाया बल्कि वर्ग

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, January 2026 Impact Factor: 8.2

चेतना और सामाजिक समानता की अवधारणाओं को भी मजबूत किया। आधुनिक भारत की वर्तमान सामाजिक असमानताएँ, शहरी स्तरीकरण और औद्योगिक वर्ग संघर्ष इसी ऐतिहासिक परिवर्तन की निरंतरता को दर्शाते हैं।

संदर्भ सूची

1. बेली, सी.ए. (2004). द बर्थ ऑफ़ द मॉडर्न वर्ल्ड. ब्लैकवेल पब्लिशिंग.
2. चंद्रावरकर, आर. (1994). द ओरिजिन्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़्म इन इंडिया. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. डेविस, एम. (2006). प्लैनेट ऑफ़ स्लम्स. वर्सो.
4. हार्वे, डी. (2011). द एनिग्मा ऑफ़ कैपिटल. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
5. ओमवेट, जी. (1994). दलित्स एंड द डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन. सेज पब्लिकेशन्स.
6. पैरी, जे. (2013). इंडस्ट्रियल वर्क एंड लाइफ़ इन कंटेम्पररी इंडिया. कैम्ब्रिज.
7. रॉय, टी. (2016). इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, 1857–1947. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
8. सेन, ए. (1999). विमेन एंड लेबर इन इंडिया. सेज पब्लिकेशन्स.